बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India



आशाएँ हों साकार
CONNECTING ASPIRATIONS

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

निदेशक मंडल BOARD OF DIRCETORS



श्री एन दामोदरन (कार्यपालक निदेशक), श्री नीरज भाटिया, श्री संजीव अरोड़ा, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू,
श्री दीनबंधु मोहापात्रा, (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ), श्री ए. के. दास (कार्यपालक निदेशक), श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष),
श्री आर. ए. शंकर नारायणन (कार्यपालक निदेशक), श्रीमती वेनी थापर, श्रीमती आर. सेबास्टियन

Shri N Damodharan (ED), Shri Neeraj Bhatia, Shri Sanjiv Arora, Shri Girish Chandra Murmu,
Shri Dinabandhu Mohapatra (MD & CEO), Shri A K Das (ED), Shri G Padmanabhan (Chairman),
Shri R A Sankara Narayanan (ED), Ms. Veni Thapar, Ms. R Sebastian

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोनः 022 - 6668 44 44
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइटः www.bankofindia.co.in

HEAD OFFICE:
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone: 022 - 6668 44 44
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	8 जुलाई, 2017 सुबह 10:00 बजे से 10 जुलाई, 2017 शाम 05:00 बजे तक	E- Voting dates	8th July, 2017 10 a.m. to 10th July, 2017 Till 05:00 p.m.
लेखाबंदी तिथि	8 जुलाई, 2017 से 11 जुलाई, 2017	Book Closure	8th July, 2017 to 11th July, 2017
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	मंगळवार, 11 जुलाई, 2017 सुबह 10:30 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Tuesday 11th July, 2017 at 10:30 a.m.
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	सांविधिक लेखा परीक्षक	2	Statutory Auditors
2	महाप्रबंधक	2	General Managers
3	अध्यक्ष का संबोधन	3	Chairman's Statement
6	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संबोधन	6	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

10	निदेशक रिपोर्ट	12	Directors' Report
14	प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण	23	Management Discussion & Analysis
31	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट	31	Corporate Social Responsibility Report
32	कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	32	Corporate Governance Report
50	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण	50	CEO/CFO Certificate
50	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	50	Declaration by CEO
156	बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन	191	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
224	आम बैठक की सूचना	224	Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

52	तुलनपत्र	52	Balance Sheet
53	लाभ एवं हानि खाता	53	Profit & Loss Account
54	नकदी प्रवाह विवरण	54	Cash Flow Statement
62	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	62	Significant Accounting Policies
73	लेखे पर टिप्पणियां	73	Notes Forming Part of Accounts
111	स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट	111	Independent Auditor's Report
115	समेकित वित्तीय विवरण	115	Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	M/s. Grover Lalla & Mehta
मेसर्स बी रतन एण्ड एसोशिएट्स	M/s. B Rattan & Associates
मेसर्स जी डी आपटे एण्ड कंपनी	M/s. G D Apte & Co.

महाप्रबंधक General Managers

के. सेल्वराज (सीवीओ)	K. SELVARAJ (CVO)
पी. के. पट्टनाइक	P. K. PATTANAIK
संजय पवार	SANJAY PAWAR
शंकरदास गुप्ता	SHANKARDAS GUPTA
एस. आर. मीणा	S. R. MEENA
के. बी. जैन	K. B. JAIN
टी. सुधाकर	T. SUDHAKAR
एस. के. कासलीवाल	S. K. KASLIWAL
एस. सी. मोदी	S. C. MODI
एस पलनिवेल	S. PALANIVEL
बी. के. मोहन्ती	B. K. MOHANTY
आई. एम. मलिक	I.M. MALIK
ए. के. आज़ाद	A.K. AZAD
डी. के. गर्ग	D.K. GARG
सी. जी. चैतन्य	C. G. CHAITANYA
आर. एस. चौहान	R.S. CHOUHAN
एस. सी. षडंगी	S.C. SARANGI
रमन के. शर्मा	RAMAN K. SHARMA
एम. के. गुप्ता	M.K. GUPTA
एस. सी. बनिक	S.S. BANIK
के. आर. नायर	K.R. NAIR
आर. सी. ठाकुर	R.C. THAKUR
एस. के. अग्रवाल	S.K. AGGARWAL
पी. ए. जोशी	P.A. JOSHI
आर. के. मित्रा	R.K. MITRA
डी. पी. मिश्रा	D.P.MISHRA
शीला सैल	SHEELA SAIL
एस. के. मुखर्जी	S.K. MUKHERJEE
आर. पी. गुप्ता	R.P. GUPTA
आर. एम. कदम	R.M. KADAM
आर. गणेशन	R. GANESAN
एम. के. श्रीवास्तव	M. K. SRIVASTAVA
अरविंद वर्मा	ARVIND VERMA
सुधाकर कैमल	SUDHAKAR KAIMAL
मनोज कपूर	MANOJ KAPOOR
शंकर अय्यर	SHANKER IYER
विश्वनाथ गुंटा	VISWANATH GUNTA
स्वरूप दासगुप्ता	SWARUP DASGUPTA
ए. के. अरोरा	A.K. ARORA
एस. रवि कुमार जोयसुला	S. RAVI KUMAR JOSYULA
एस. के. स्वाईं	S. K. SWAIN
जे. के. श्रीवास्तव	J. K. SRIVASTAVA
ए. के. पुन	A.K. PUNN

अध्यक्ष का संबोधन
Chairman's Statement



प्रिय शेयरधारकों और पणधारकों,

1. विगत वित्तीय वर्ष में घरेलू एवं वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में कई गतिविधियाँ हुई हैं। नि:संदेह जिन प्रमुख गतिविधियों ने विश्वभर का ध्यान आकर्षित किया वे हैं 1) संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 2) ब्रेक्सिट वोट जो यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच वित्तीय और कूटनीतिक रिश्तों को बदलने की क्षमता रखता है। 2016 की अंतिम तिमाही में यूएस अर्थ व्यवस्था ने 3 प्रतिशत जीडीपी बढ़ोत्तरी के साथ प्रभावी वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि वार्षिकीकृत आधार पर जनवरी-मार्च 2017 में इसमें 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है। तथापि बेरोजगारी की दर घटकर 4.5 प्रतिशत हुई है और यूएस फेडरल रिजर्व में 25 बीपीएस की वृद्धि हुई है। ईयू में धीमे सुधार का वातावरण है जबकि जापान में मुद्रा अपस्फीति का दौर जारी है। चीन में 6.5-7 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है। यूएस जिसने दरों में वृद्धि की इच्छा के संकेत दिए हैं, को छोड़कर अधिकतर केन्द्रीय बैंक अभी भी विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

2. जहाँ तक घरेलू मोर्चे का संबंध है, यह अपेक्षित है कि भारत की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहेगी और इस प्रकार वह विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। मैक्रो इकॉनॉमिक मानदंड सुदृढ़ हुए हैं, एफडीआई का अंत:प्रवाह रिकार्ड स्तर पर डॉलर 43 बिलियन रहा, चालू खाता घाटा 1.5 प्रतिशत से कुछ नीचे रहा और केन्द्र तथा राज्यों दोनों के राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन एक्ट सहित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहा। सीपीआई मुद्रा स्फीति 3 प्रतिशत से कम रही और तेल की घटती कीमतों के कारण यह 2 प्रतिशत भी हो सकती है। संशोधित आधार वर्ष में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 2.7 प्रतिशत रही जो गत वर्ष से अधिक है, फारेक्स रिजर्व रिकार्ड स्तर पर $ 370 बिलियन रहे जो करीब एक वर्ष के आयात कवर हेतु पर्याप्त है। कारोबार करने में सहजता के अन्तर्गत रैंकिंग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संकेत गत वर्षों से लगातार बेहतर हो रहे हैं। वार्षिक आधार पर 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रोजगार निर्माण का क्षेत्र अभी भी एक बड़ी

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. Over the past financial year, a slew of developments have defined the domestic and global financial landscape. Undoubtedly, the major developments which caught attention at a global level were 1) the U.S. Presidential elections and 2) the Brexit vote which has the potential to alter the contours of financial and diplomatic relations between the U.K and European Union. U.S economy posted impressive growth during the last quarter of 2016, with a GDP growth of more than 3% which, however, nosedived to 0.7% on an annualized basis during January-March 2017. However, unemployment rate declined to 4.5% and prompted a 25 bps rate hike by the U.S. Federal Reserve. EU meanwhile, is nudging along with growth a shade into positive territory while Japan continues to be in deflation zone. China is expected to grow between 6.5-7%. Most central banks are still pursuing an expansionist monetary policy with the exception of U.S which has indicated its willingness for further rate hikes.

2. On the domestic front, India is expected to post a growth rate of more than 7%, thus retaining the tag of the fastest growing economy in the world. Macroeconomic parameters are on a sound footing: FDI inflows are at a record $43 billion, Current Account Deficit is just a shade below 1.5% and fiscal deficit is contained at 3.5% of GDP with the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) also in place for both the Centre and the states. CPI inflation is below 3% and may even reach 2% due to sliding oil prices. The revamped base year has shown industrial production growth at 2.7%, higher than previous years; Forex reserves are at a record $ 370 billion, enough for almost a year of import cover. Rankings under 'ease of doing business' and competitiveness indices are continuously showing an improvement over the previous years, to name a few. A big challenge is on the job creation

चुनौती है। उद्यमिता के वातावरण का निर्माण करने के लिए स्टार्टअप हेतु फंड ऑफ फंड का सृजन किया गया।

3. अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। यह स्वीकार करना होगा कि इस क्षेत्र हेतु कई चुनौतियाँ हैं। मार्च 2017 में वर्ष दर वर्ष बैंक क्रेडिट 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार कमजोर बनी रही। विशेषरूप से उद्योगों को ऋण देना कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ। जबकि गत वर्ष की तुलना में बैंकों के एमसीएलआर में लगभग 100 बीपीएस की कमी हुई है। कम मांग के कारण सुस्त औद्योगिक क्षमता और आस्ति गुणवत्ता के कारण बैंकों के प्रभावित होना ये इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण रहे हैं। मुख्य क्षेत्र जैसे स्टील, बिजली और टेक्सटाइल में अभी तेजी आना शेष है जबकि टेलीकॉम ऐसा नया क्षेत्र है जहाँ जोखिम बढ़ा है। नोटबंदी के कारण उत्पन्न चलनिधि आधिक्य से ऋण एवं जमा दोनों की दरों को कम करने में मदद मिली है और बांड का प्रतिफल भी कम हुआ जिससे बैंक के कोषागारों को अप्रत्याशित लाभ हुआ है। बैंकिंग प्रणाली में सकल एनपीए बढ़कर ₹ 7 लाख करोड तक पहुँच गया है जिसमें से अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। भारत सरकार ने रुग्ण बैंकों को सहायता देने के उद्देश्य से ₹ 10,000 करोड़ बजट में रखे हैं परन्तु वर्तमान परिवेश में ऐसा प्रतीत होता है कि इन बैंकों को उबारने के लिए और पूँजी देने की आवश्यकता होगी।

4. हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख परिवर्तनकारी तथ्य डिजिटल ट्रांसफारमेशन की ओर बढ़ना रहा है जो अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग परिदृश्य पर छा गया। इसमें नोटबंदी का अभियान भी जुड़ गया। इसका उद्देश्य है कि एक दशक के अंदर नकदी रहित लेन-देन 10 प्रतिशत के आसपास पहुँच जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पहल की गई हैं जैसे कुछ इस प्रकार हैं - एमडीआर चार्ज न लेना, ₹ 2 लाख से अधिक नकद भुगतान न करना, चुनाव निधि हेतु ₹ 2000 से अधिक नकद राशि देने पर रोक, इलेक्टॉरल बॉड्स जारी करना आदि। बैंकिंग क्षेत्र में इन सबका असर निश्चित ही देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक चेनल को अपनाएंगे जिससे शाखओं में आने वाले लोगों की संख्या कम होगी। डिजिटल अभियान के बाद भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक पहले ही मार्केट में पकड़ बनाने के लिए आ गए हैं। इस परिदृश्य में विभिन्न पदधारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए नवोन्मेषी बनना होगा।

5 विगत कुछ वर्षों में 5/25 योजना एसडीआर योजना एवं एस 4 ए संबंधी पहल निश्चित ही अभिनव कार्य हैं। यद्यपि आस्ति गुणवत्ता की गिरावट संबंधी मामलों में इन साधनों की सफलता सीमित है तथापि एक्यूआर संबंधी कार्रवाई में अपचार से लड़ने में इनसे बैंकों को मदद मिलती हो। हालाँकि भारत सरकार आस्ति गुणवत्ता संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए पूरक प्रयास के रुप में एनपीए अध्यादेश लाई है इसके अलावा जेएलएफ निर्णयों को लागू करने में पहलेके 75% के स्थान पर ऋणदाता के 60% द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता की शर्त लगाते ही समय को कम करने हेतु कदम उठाए गए है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू करना त्वरित हो गया है और विनियामक स्तर पर एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया गया है ताकि बैंकर दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान निडरता से कर सकें।

6. दो प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाए, वे हैं बैंकों में मानव संसाधन की स्थिति एवं बोर्ड तथा प्रबंधन का वृत्ति दक्षताकरण (प्रोफेसनाइलेशन), दिवाला एवं शोधन अक्षमता बैंकिंग एक ऐसा

front with employment generation growing at 1% on a yearly basis. A Fund of Fund (FoF) for startups has been created to form an entrepreneurial climate.

3. Being an integral part of the economy, banking sector has been given a major thrust. To start with, it has to be admitted that the scenario is a bit challenging. Bank credit growth continues to be anaemic with growth being 8% year-on-year for the year ended March 2017. Credit to industries has been particularly hit hard. This is despite the fact that MCLRs of banks have come down by around 100 bps over the past year. Idle industrial capacity due to sluggish demand and banks being hit by asset quality woes are the major reasons for this trend. Major sectors like steel, power and textiles are yet to gain traction while telecom segment has emerged as a new source of risk. Demonetization induced liquidity surge has helped lower both lending and deposit rates and lowered bond yields thus facilitating windfall gains to bank treasuries. Gross NPAs in the system has touched Rs.7 Lakh Crores with the bulk of them being accounted for by PSBs. GOI has budgeted Rs.10,000 Cr to support ailing banks but given the scenario, it seems more capital infusion would be required to salvage these banks.

4. A major game changer during the just concluded financial is the shift towards digital transformation that has enveloped the economy and banking landscape. This coincided with the demonetization drive. The objective is to bring the cashless transactions to around 10% within a decade. A number of steps towards this end have been initiated such as waiver of MDR charges, no cash payments above Rs.2 Lakh, bar on election funding of more than Rs.2000 in cash, issuance of electoral bonds etc to name a few. Banking sector would surely feel the impact of such changes with more and more customers expected to switch to electronic banking channels, significantly reducing the footfalls in branches over a period of time. Payments banks and small finance banks ae already there to grab market share post the digital drive. In this scenario, incumbents must strive hard and innovate to stay competitive and protect their turf.

5. The 5/25 scheme, the SDR scheme and the S4A initiatives are certain novel developments during the past couple of years. Though the success of these instruments in reducing the asset quality issues have been limited, it has nevertheless equipped banks with more tools to fight delinquency post the commencement of AQR exercise. However, GOI has brought forth the NPA Ordinance to complement efforts to reduce asset quality troubles. Moreover, steps have also been taken to reduce time to implement JLF decisions by stipulating the necessity of approval by only 60% of creditors by value as opposed to the earlier 75%. The Insolvency and Bankruptcy Code is becoming operational fast and an Oversight Committee has also been formed at the regulatory level to aid fearless resolution of stressed assets by bankers

6. Two major issues which have somehow escaped attention of successive governments but which merits a look are the state of human resources in banks and professionalization of Boards and management. Banking is an evergreen

(सदाबहार) क्षेत्र है जो गतिशील वातावरण में कार्य करता है। बैंकरों को विशेषकर वरिष्ठ स्तरों पर उचित रुप से प्रतिपूर्ति करना एक प्रमुख ध्यान दिऐ जाने योग्य क्षेत्र है जिसका निराकरण होना चाहिए।

अनुभवी व्यक्ति की सेवानिवत्ति पर उसके स्थान - पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति भी एक अन्य चुनौती है। बैंकों को नए उत्पाद जारी करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। हालाँकि बैंकों को ब्याज दर विकल्प शुरु करने की अनुमति देते हुए इस दिशा में शुरुआत हो चुकी है।

7. इन सब चुनौतियाँ के बीच यह वास्तव में प्रशंसनीय है कि भारत में बैंक एक संतुलित तरीके से सामाजिक दायित्व के निर्वहन और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सफल हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2017 में किसी भी बैंक ने परिचालन हानि दर्ज नहीं की है। हमने दो गंभीर वित्तीय संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया हैं, जिनकी वजह से अमोध प्रतीत होनेवाली अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई। वर्तमान चुनौतियों केवल सिलिड्रिकल प्रकृति की हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस परिस्थिति से बिना किसी क्षति के शीघ्र ही उभर कर आएंगे।

जी. पद्मनाभन

area which operates under a dynamic environment. Compensating bankers properly should be a major focus area which needs to be addressed, especially at senior levels. Another challenge is replacement of experienced superannuating personnel. Banks must also be permitted to introduce new products. A beginning has, however, been made in this regard by permitting banks to introduce interest rate options.

7. However, amidst all these challenges, it is indeed commendable that banks in India have been able to perform a fine balancing act between their social obligations and staying competitive. It is noteworthy that no bank has posted operational loss during FY 2017. We have successfully weathered two major financial crises as well which, however, gripped seemingly infallible economies. The present challenges are only of a cyclical nature and we are expected to emerge unscathed from this scenario as well sooner than later.

G. Padmanabhan

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य
Managing Director & CEO's Statement



प्रिय शेयरधारी और हितधारक,

1. आपके बैंक की 21 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. आप जानते ही हैं कि हाल ही में मैंने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। हमने पिछले वर्ष में हानि को काफी कम किया है। विनियामक और सरकार द्वारा की जा रही पहल और हमारे समर्पित स्टाफ सदस्यों द्वारा किए जा रहे प्रयास से शीघ्र ही कायापलट अवश्य होगी। मैं सहर्ष आप के समक्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मेरा यह मानना है कि यदि कोई बात नियत है, तो वह है परिवर्तन। हम यदि अपने चारों ओर के वातावरण पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट होगा। विदेशों में भी हमारा अस्तित्व है, अत: हम विश्व के परिदृश्य से ही शुरुआत करते हैं। दो वित्तीय केन्द्रों में बड़े परिवर्तन हुए हैं यथा यू. एस और यू. के; पूर्ववर्ती मामले में राष्ट्रपति के निर्वाचन में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए और दूसरा ब्रेकसिट के परिणामों से घिरा हुआ था। इसके दूरगामी प्रभाव भिन्न देशों तक हुए हैं और हम भी इससे अछूते नहीं रहे। भिन्न क्षेत्रों में नीतियों के साथ-साथ, सभी अर्थव्यवस्थाओं में विकास का परिदृश्य एक समान नहीं है। यू.एस ने जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% की कमी दर्शायी है और ई.यू किसी प्रकार सकारात्मक स्थिति बनाए रखने में सफल रही। जापान में अपस्फीति है और चीन में विकास दर धीमी रही और वह 7% से कम हुई है, जो व्यापक शैडो बैंकिंग से ग्रस्त है जो 220 अरब डॉलर है। यू.एस फेडरल रिजर्व ने प्रधान नीतिगत दर 25 बीपीएस बढ़ाई है, जबकि ईयू और जापान में सेंट्रल बैंक इस हेतु अनिच्छुक हैं क्योंकि जो विकास उन्होने भिन्न प्रोत्साहनों से प्राप्त की है उसे खोना नहीं चाहते। इस परिदृश्य में भारत के निवेशकों को सर्वाधिक ब्याज दर प्राप्त हो रही है, 10 वर्ष के बेंचमार्क, 6.76% प्रतिफल दे रहा है।

3. **घरेलू अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है ...**

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले तीन वर्षों में लंबी छलांग लगायी है। किसी भी

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 21st Annual General Meeting of your Bank. As you are all aware, I have only recently taken over as the MD & CEO of your Bank. We have significantly erased our losses over the past year. Various initiatives by the Regulator and GOI as well as by our own dedicated staff will ensure a turnaround as soon as possible. It gives me great pleasure to place before you the annual report of your Bank for the year ended March 31, 2017.

2. I believe that if there is a constant, it is only change. It will be amply clear just by a cursory glance at the environment around us. Since we have overseas presence as well, let us start by observing at the global landscape. Massive changes have swept two leading financial centres - the U.S. and the U.K.; the former due to the surprising outcome of her Presidential elections and the latter engulfed by the Brexit result. This has had far reaching ramifications across several countries and we are not immune to those. Apart from policies on various sectoral fronts, growth outlook is not uniform across economies. While the US has shown a decline to 0.7% annualized rate of GDP growth for January-March period, EU just manages to stay in the positive territory. Japan continues to face deflation while China has slowed down to below 7%, plagued as it is by a massive shadow banking system worth $ 220 billion. While the US Federal Reserve has raised the key policy rate by 25 bps, central banks in EU and Japan are reluctant for fear of losing whatever growth they have managed through stimulus measures. In this backdrop, India earns investors the highest rate of interest with our 10 year benchmark yielding 6.76%.

3. **Domestic economy gathers momentum.....**

Indian economy has undoubtedly leapfrogged over the past

मैक्रो मानदंड पर नज़र डालें और यह दृष्टिगोचर होता है। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वित्तीय वर्ष 18 में 7.5% छूने को तैयार है और चालू खाते की घाटा 1.5% से कुछ कम किया गया है, जो 2014 के पूर्व 4% के उच्च स्तर पर था। वित्तीय घाटा 3.5% से नीचे है : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की आवक सबसे अधिक देखी गई हैं जो 43 अरब डॉलर हैं : विदेशी मुद्रा रिजर्व सर्वाधिक देखी गई हैं, 370 अरब डॉलर हैं। कारोबार करने में आसानी संबंधी श्रेणी में हमारा स्थान बेहतर हुआ है और प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड का उल्लेख अक्सर किया गया है और यहाँ उसका जिक्र करना निरर्थक है। सफलता का एक प्रमुख कारण है राजनयिक संबंधों में सुधार हेतु किए गए अतिबृहत प्रयास जिसके फलस्वरूप हमने आर्थिक लाभ प्राप्त किए हैं। इन सबके बीच हमने जिन प्रमुख समस्याओं का सामना भी किया वे हैं धीमा पूंजी निर्माण, उद्योग द्वारा क्षमता का कम उपयोग, रोज़गार सृजन और दोहरी तुलन पत्र समस्या (बैंक एवं कॉरपोरेट)। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने हेतु युद्ध स्तर पर भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

4. **बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संभावनाये हैं** ....

बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य पूर्व वर्षों की अपेक्षा काफी भिन्न है। बैंक ऋण विकास दर 8.7% के ऐतिहासिक निचली दर पर है और उत्पाद क्षेत्र को ऋण में 1.9% की कमी आयी है जबकि वित्तीय वर्ष 16 में 2.2% की वृद्धि थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण क्षेत्र में हिस्सेदारी काफी घट गई है, उनकी हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 17 में 71.8% थी जबकि वित्तीय वर्ष 15 में यह 77.8% थी। यह उद्योग स्तर पर कम क्षमता का उपयोग और त्रुटिपूर्ण आस्तियों के कारण भी है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात औसतन बैंक स्तर पर बढ़े हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पिछले वर्ष की तुलना में हानि काफी कम हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक समूह के रूप में इस वर्ष भी हानि दर्शाई है।

5. विमुद्रीकरण पर विचार करना यहाँ प्रासंगिक होगा। इससे तरलता अधिक हो गई, बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई और एमसीएलआर कम हुई है। वर्ष के दौरान एक वर्ष की बैंक जमा दर 7-7.5% की दर से 6.5-7% हुई है। एमसीएलआर 100-110 बी पी एस कम हुई है। कम ब्याज दरों के कारण खुदरा ऋण में तेज़ी से वृद्धि हुई है जबकि ब्याज की आय में वृद्धि औद्योगिक स्तर पर नगण्य थी।

6. में यहाँ इस तथ्य पर ज़ोर देना चाहूँगा कि बैंक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते वक्त हमें निवल लाभ से जुड़े जुनून को त्यागना होगा और परिचालन लाभ को मूल मापदंड मानना होगा। औद्योगिक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों सहित सभी बैंकों ने मिलकर सभी ने परिचालन लाभ में अच्छी वृद्धि दर्शाई है। यह बैंक के मामले में भी सही है। निवल हानि का संबंध उच्च प्रावधान से है जो चक्रीय क्षेत्रों से सम्बद्ध होने के कारण है जिनके भविष्य में बदलने की क्षमता है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापक मध्यस्थता संबंधी लागत जो सामाजिक बाध्याताओं के कारण है, इसके बावजूद बैंक परिचालन स्तर पर लाभ दर्शा रहे हैं। यह ऐसा तथ्य है जिसे भिन्न मंचों पर उजागर नहीं किया गया है। यह केवल कुछ समय की बात है जिसके पश्चात हमारा सम्पूर्ण कायाकल्प होगा। जब यह संकटग्रस्त क्षेत्र संकट से उबरकर निकलेगा।

7. यह मूलत: भिन्न पहलों द्वारा पूरित किया जाएगा। दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता अपने व्यावहारिक स्वरूप में तेज़ी से बदला जा रहा है। इसे पूरी क्षमता तक उपयोग में लाने के लिए कुछ समय लगेगा, इसमें प्रशिक्षित कार्मिक, संभार तंत्र, और आसूचना उपयोगिताओं को स्थापित करना आवश्यक है। इस दौरान आरबीआई कुछ कदमों के साथ आया है जिससे जे एल एफ के मामलों का निपटान तेज़ी से किया जा सके और निरीक्षण समिति

three years. Look at any macro parameter and it is visible. GDP growth is set to touch 7.5% for FY 18; Current Account Deficit has been brought down to a shade below 1.5% from the highs of 4% seen before 2014: Fiscal deficit is below 3.5%: Foreign Direct Investments (FDI) inflows are one of the highest recorded ever at $ 43 billion: Foreign reserves are at an all-time high of $370 billion. The improvements in rankings under 'ease of doing business' and Competitiveness Indices have been cited often and it would be redundant to dwell upon that here. A key success factor is the tremendous strides that have been achieved in diplomatic outreach which in turn translates into economic gains. Amidst all this, slow capital formation, low capacity utilization by industry, employment generation and the twin balance sheet problem (banks and corporates) are the major sticking points. Efforts are earnestly underway to address these issues on a war footing.

4. **Banking sector holds great promise….**

Coming to the banking sector, the macro scenario is somewhat different from what it used to be a couple of years before. Bank credit growth is at a historic low of 8.7% with credit to manufacturing segment showing a decline of 1.9% vis-à-vis a growth of 2.2% during FY 16. Public Sector Banks have lost significant market share with their share in credit at 71.8% during FY 17 compared to 77.8% during FY 2015. This may be attributed to low capacity utilization at the industry level and also to delinquency in assets. Gross NPA ratios have increased though at the aggregate bank level and across public sector banks losses have declined significantly over the previous year. PSBs as a group, however, continued to post losses this year as well.

5. It would be pertinent to dwell upon the demonetization issue. This led to a liquidity surplus scenario and bond yields as well as MCLRs declined. During the year one-year bank deposit rate declined from the range of 7-7.5% to 6.5-7%. MCLRs declined by 100-110 bps. Moderation in lending rates translated into faster growth in retail lending though interest income showed only muted growth at the industry level.

6. I wish to state here that while assessing bank performance, we must shed our obsession with net profit and watch operating profit as the key metric. Needless to mention, at the industry level, all banks including PSBs have showed good growth in operating profit. The same holds true for Bank as well. The net loss is attributable to higher provisioning necessitated on account of exposure to cyclical sectors which has the potential for a turnaround in the future. It is remarkable that despite incurring huge intermediation costs on account of our social obligations, banks continue to post profits at the operating level. This is something which is not adequately highlighted at various fora. It is only a matter of time before which we post an absolute turnaround when the troubled sectors come out of the woods.

7. This will be complemented by various initiatives on the ground. The Insolvency and Bankruptcy Code is evolving into its practical application at a very fast pace. However, its full potential is still a few years away due to the need for trained personnel, logistics and the need to set up information utilities .Meanwhile, the RBI has come out with

प्रणाली जो बैंकरों को निडर होकर दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में सहायता करती है। इसे हाल में संसद द्वारा पारित एनपीए अध्यादेश को परिचालन में लाने हेतु किए गए त्वरित उपाय के रुप में देखा जाना चाहिए।

8. आपके बैंक के कार्यनिष्पादन को उपरोक्त उभरते परिदृश्य के संदर्भ में देखना चाहिए। समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय तथ्य आशाजनक थे.आपके बैंक की निवल हानि तीन गुना कम हुई है। आस्तियों की गुणवत्ता स्थिर हुई है और घरेलू स्तर पर मार्जिन में सुधार हुआ है। आपके बैंक ने परिचालन लाभ में 61.25% की वृद्धि दर्शाई है जो वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थियों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

9. इस परिदृश्य में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की विस्तृत वित्तीय स्थिति सहर्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके बैंक ने कई प्रमुख पैमानों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

10. **बैंक का कार्यनिष्पादन**

- आपके बैंक का वैश्विक कारोबार यथा 31.03.2017 को ₹ 933,820 करोड़ रहा ।
- आपके बैंक की कम लागत की जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 30.24% की वृद्धि हुई है और घरेलू जमाराशियों में उसकी हिस्सेदार जो मार्च 2016 में 34.18% थी बढ़ कर मार्च, 2017 में 39.84% हो गई।
- सकल अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष 3.18% एवं तिमाही-दर-तिमाही 1.75% वृद्धि के साथ ₹ 393,788 करोड़ पर हैं।
- रिटेल योजनाबद्ध ऋण वर्ष-दर-वर्ष 10.63% वृद्धि के साथ यथा 31 मार्च, 2017 को ₹ 41,793 करोड़ पर रहे। कुल घरेलू अग्रिमों में रिटेल ऋणों की हिस्सेदारी जो मार्च, 2016 में 14% थी बढ़कर मार्च, 2017 में 15% हो गई।
- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 113,027 करोड़ पर रहे जो एएनबीसी का 40.47% है, कृषि अग्रिम ₹ 54,303 करोड़ पर रहे जो एएनबीसी का 19% है।
- बैंक की कुल मीयादी जमाराशियों में ₹ 1 करोड एवं उससे कम की रिटेल मीयादी जमाराशियों की हिस्सेदारी 76% है।
- बैंक का वैश्विक सकल एनपीए अनुपात जो दिसंबर 2016 में 13.38% था क्रमिक रुप से घट कर यथा 31 मार्च, 2017 को 13.22% हो गया. वैश्विक निवल एनपीए अनुपात जो 31 दिसंबर, 2016 को 7.09% या घटकर अब 6.90% हो गया है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात जो मार्च, 2016 मे 51.14% था सुधरकर मार्च, 2017 में 61.47% हो गया।
- बैंक का परिचालन लाभ जो 31 मार्च, 2016 को ₹ 6,036 करोड था वर्ष-दर-वर्ष 61.25% वृद्धि के साथ के ₹ 9,733 करोड हो गया।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ -1558 करोड़ के कर पश्चात लाभ की घोषणा की है, जबकि विगत वर्ष इसी अवधि के लिए कर पश्चात लाभ ₹ -6,089 करोड था। इस प्रकार बैंक ने हानि को 74.41% कम किया है।
- निवल ब्याज आय (NII) जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11,725 करोड़ था वर्ष-दर-वर्ष 0.87% वृद्धि के साथ ₹ 11,826 करोड़ हो गया है।
- घरेलू परिचालनों पर निवल ब्याज मार्जिन (NIM) जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.50% था, सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2.60% हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी परिचालनों पर निवल ब्याज मार्जिन 1.25% था। समग्र रुप में वैश्विक एनआईएम जो वित्तीय वर्ष 2015-16 मे 2.11% था सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 मे 2.20% हो गया।

measures aimed at faster resolution of JLF cases and the Oversight Committee mechanism which aids bankers in fearless resolution of stressed assets. This has to be seen as a swift measure to operationalize the NPA Ordinance enacted recently by the Parliament.

8. The performance of your bank also has to be viewed against the above unfolding landscape. The financials for the just concluded year were promising. Your bank has shown a three fold reduction in net loss. Asset quality has stabilized and margins at the domestic level have improved. Your bank has shown a growth of 61.25% in operating profit which is not a mean achievement during these volatile times.

9. With this backdrop I have great pleasure in presenting before you the detailed financials for the year ended 31 March 2017. Your Bank has achieved impressive strides under several key parameters.

10. **BANK'S PERFORMANCE**

- Your Bank posted an overall Global Business of the Bank stood at ₹ 933, 820 crore as on March 31, 2017.
- Your Banks Low Cost Deposits (CASA) grew by 30.24% YoY and its share in Domestic deposits improved from 34.18% in March 2016 to 39.84% in March 2017.
- The Gross Advances at ₹ 393,788 crore, grew by 3.18% YoY and 1.75% QoQ.
- Retail schematic Loans increased by 10.63% YoY and stood at Rs 41,793 crore as on March 31, 2017. Retail Loans share in Total Domestic Advances increased YoY, from 14% in March 2016 to 15% in March 2017.
- Priority Sector advances stood at ₹ 113,027 crore which constitutes 40.47% of ANBC. Agriculture advances were Rs 54,303 crore forming 19% of ANBC.
- The share of Retail Time Deposits of ₹ 1 crore and less constitutes 76% of Bank's total time deposits.
- Bank's Global Gross NPA ratio declined sequentially and was 13.22% as on March 31, 2017 as against 13.38% as on December 2016. Global Net NPA ratio declined to 6.90% as against 7.09% on December 31, 2016.
- The Provision Coverage Ratio improved from 51.14% in March 2016 to 61.47% in March 2017.
- The Bank's Operating Profit as on March 31, 2017 is ₹ 9,733 crore as against ₹ 6,036 crore as on March 31, 2016 showing YoY growth of 61.25%.
- The Bank declared PAT of ₹ -1,558 crore in FY2016-17 as against ₹ -6,089 crore PAT for corresponding period last year, reduced the loss by 74.41%.
- NII during FY 2016-17 has improved to ₹ 11,826 crore as compared to ₹ 11,725 crore in FY 2015-16, an increase of 0.87% YoY.
- Net Interest Margin (NIM) on domestic operations has improved from 2.50% in FY 2015-16 to 2.60% in FY 2016-17. NIM on overseas operations was 1.25% for FY 2016-17. Overall the global NIM has improved to 2.20% in FY 2016-17 from 2.11% in FY 2015-16.
- Non-Interest Income during FY 2016-17 has improved